

कोई कार्यवाही किसी निष्कर्ष पर पहुँच कर करती है तो वह उचित नहीं होगा।

हमने कमीशन से निवेदन किया है कि मार्च तक अपनी रिपोर्ट दे दें। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई होगी तो उसको किसी भी तरह से क्षमा नहीं किया जायेगा बल्कि जितनी भी सख्ती के साथ उसको दण्डित किया जा सकता है, दण्डित किया जायेगा। 10

जहां तक कर्मचारियों के आश्रितों को पुनः स्थापित करने का प्रश्न है, मैं इस पर निश्चित रूप से विचार करूँगा। मैं इस बात को सदन की जानकारी में ला दूँ कि जो कुछ मुआवजा मिलने वाला था वह किसी भी छोटे से छोटे कर्मचारी को कम से कम एक लाख से कम मुआवजा न मिले—इसके लिए मैं ने तत्काल एग्जर इंडिया को निर्देश दिए थे। प्रत्येक परिवार के आश्रितों को पचास हजार रुपये एक्स-ग्रेडिया देने की बात कही थी। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से भी जितना भी हम कर सकते हैं, हमने करने की कोशिश की है। उन परिवारों को व्यवस्थित ढंग से चलाने और जो लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनकी शिक्षा के लिए तथा किसी भी छोटे मोटे व्यवसाय के लिए यह राशि पर्याप्त होगी।

14.37 hrs.

DEPOSIT INSURANCE CORPORATION  
(AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) BILL\*

THE MINISTER OF FINANCE  
AND REVENUE AND BANKING  
(SHRI H. M. PATEL): I beg to move

for leave to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of the undertaking of the Credit Guarantee Corporation of India Limited in order to serve better the need for providing credit guarantee to commercial banks, and further to amend the Deposit Insurance Corporation Act, 1961, and the Reserve Bank of India Act, 1934, and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of the undertaking of the Credit Guarantee Corporation of India Limited in order to serve better the need for providing credit guarantee to commercial banks, and further to amend the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 and the Reserve Bank of India Act, 1934, and for matters connected therewith or incidental thereto."

*The motion was adopted.*

SHRI H. M. PATEL: I introduce the Bill.

14.38 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED DECISION OF THE CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES TO STAGE *Dharnas*

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): With your permission under Rule 377, may I draw the attention of the hon. House and the Government to the decision taken by the Central Government employees to organise joint mass *dharnas* on 23rd March, 1978 as a first step to their agitation

\*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 21-2-78.

†Introduced with the recommendation of the President.